भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2717

19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए नियत

फेम इंडिया योजना

2717. श्रीमती रंजीता कोली:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेम इंडिया का भारत में (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) योजना के कार्यान्वयन और परिणामों के बारे में विशेष विवरण क्या है और खरीदारों को दिए जाने वाले सटीक प्रोत्साहन क्या हैं और देश में 2015 में इसकी शुरूआत के बाद से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में कितना विस्तार हुआ है;

(ख) 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से फेम इंडिया पहल को कुल कितना बजट आबंटित किया गया है; और

(ग) फेम इंडिया पहल के तहत चार्जिंग स्टेशनों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल लागू की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम तैयार की। इस स्कीम का चरण-I कुल 895 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध था। फेम इंडिया स्कीम के इस चरण के चार मुख्य क्षेत्र थे- प्रौद्योगिकीय विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना घटक।

स्कीम के पहले चरण में, लगभग 2.8 लाख एक्सईवी के लिए मांग प्रोत्साहन के तौर पर कुल 359 करोड़ रुपये (लगभग) की सहायता प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, स्कीम के पहले चरण के तहत स्वीकृत 425 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें लगभग 280 करोड़ रुपये के सरकारी प्रोत्साहन से देश के विभिन्न शहरों में परिनियोजित की गई हैं। भारी उद्योग मंत्रालय

ने फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत लगभग 520 चार्जिंग स्टेशनों/अवसंरचना के लिए भी लगभग 43 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी थी।

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), आईआईटी-मद्रास, आईआईटी-कानपुर, अलौह धातु प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (एनएफटीडीसी), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) आदि जैसे विभिन्न संगठनों/संस्थानों को परीक्षण अवसंरचना की स्थापना, विद्युतीकृत परिवहन में उन्नत अनुसंधान के लिए 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना, बैटरी इंजीनियरिंग आदि जैसी प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

फेम इंडिया स्कीम, चरण-I के दौरान प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर तथा उद्योग और उद्योग संघों सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को अधिसूचित किया है। इस चरण में मुख्यतः सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य मांग प्रोत्साहन के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों हेतु सहायता प्रदान करना है।

दिनांक 15.12.2023 की स्थिति के अनुसार, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 11,96,203 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए 5356.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है (http://fame2.heavyindustries.gov.in/dashboard.aspx के अनुसार)।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न शहरों/एसटीयू/राज्य सरकार की इकाइयों को अंतःशहरी प्रचालनों के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसें संस्वीकृत की हैं। 29 नवंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, इन 6862 ई-बसों में से 3487 ई-बसों की आपूर्ति एसटीयू को की जा चुकी है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने 7,432 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 800 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। साथ ही, इस स्कीम के अंतर्गत अन्य संस्थाओं के लिए 148 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए थे।

*****